Setting up of a Paper Mill in Orissa

2795. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a paper mill in Orissa;

(b) if so, the name of the place in Orissa where such paper mill is going to be set up;

(c) the production capacity of the proposed paper mill annually; and

(d) the progress made so far in setting up that paper mill?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) The Central Government have no proposal under consideration at present to set up a Paper Mill in the States of Orissa.

(b) to (d). Do not arise.

फरार स्वतंत्रता सेनानियों को बिहार द्वारा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी

2796. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन्हीं फरार सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर करने का है जिनके लिए स्वतन्त्रता सैनिकों द्वारा सिफारिश की गई हैं जो कम से कम पांच वर्षों तक जेलों में रहे ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने ऐसे कुछ स्वतन्त्रता सैनिकों को प्राधिकृत किया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्वतन्त्रता सैनिकों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इनमें से कुछ स्वतन्त्रता सैनिकों ने अत्यधिक रिश्वत ले कर पेंशन के लिए जाली नामों की सिफारिशें की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे स्वतन्त्रता सैनिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया): (क) जेल से भाग निकलने वाला कोई स्वतन्त्रता सेनानी 1972 की योजना के अन्तर्गत भी पेंशन के लिए पात्र था बशर्ते कि वह 6 महीने से कम भूमिगत न रहा हो और वह (i) घोषित अपराधी हो अथवा (ii) उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किया गया हो (iii) वह जिसकी नजरबन्दी का आदेश जारी किया गया हो किन्तु तामील न किया गया हो । 1980 की योजना में केवल निर्धारित अपेक्षा में छूट इस सीमा तक की गई है कि दावे के समर्थन के लिए जहां सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे, 5 वर्ष की जेल यातना वाले प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी से प्रमाण-पत्र स्वीकार्य है ।

(ख) और (ग). योजना के अन्तर्गत किसी प्रमाणकर्ता को प्राधिकृत करने के लिए राज्य सरकारों के पास कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि उपर्युक्त रियायत के अनुसरण में राज्य सरकारों से ऐसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की सूची भेजने के लिए कहा गया है जिन्होंने 5 वर्ष या इससे अधिक की सजा काटी हो, ताकि भारत सरकार उनके मामलों पर अन्तिम निर्णय ले सके जिन आवेदकों ने सजा काटने का दावा किया है । बिहार सरकार ने अभी तक ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची नहीं भेजी है जो कम से कम 5 वर्ष जेलों में रहे थे ।

(घ) और (ङ). कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अन्धाधुंध प्रमाण-पत्र जारी करने के विषय में विभिन्न लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो प्रामाण-कर्ता स्वतन्त्रता सेनानियों को कार्यक्षेत्र से मुश्किल से सम्बन्ध

रखते हो । इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुये, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अप्रैल, 1982 में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं कि केवल वास्तविक स्वतन्त्रता सैनानी ही उपर्युक्त रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकें । सरकार केवल यही कार्रवाही कर सकती है कि आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने के उद्देश्य से ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर निर्भर नहीं रहे हैं , जब तक कि दावे के समर्थन में अन्य साक्ष्य नहीं हो ।

Development of Manganese ore in the Country

2797. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for the development of manganese ore in the country since January, 1983;

(b) what is its production at present and its requirement in the country;

(c) the number of new ferro-manganese plants proposed to be set up; and

(d) the names of places where they are likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) Exploration work by Geological Survey of India (GSI) in manganese bearing areas of the country continues. Managanese Ore (India) Limited (MOIL) are also undertaking exploration work in their lease hold areas in Adilabad, A.P., in Kandri-Munsar area and Gumgaon—Beldongri mines. MOIL have also proposed to undertake exploration to prove additional resources of high grade ore in Balaghat region.

(b) The production of manganese ore as reported by Indian Bureau of Mines (IBM) is as follows:—

1981	..	15,25,000 tonnes
1982	..	14,48,000 tonnes

The consumption of manganese ore in 1980 as reported by IBM was 949,000 tonnes.

(c) and (d). MOIL have a proposal to set up a ferro manganese plant in Balaghat district of M.P.

संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की बैठक

2798. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है और उनकी मांगें कब से विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारियों की यूनियन ने मांग की है कि संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र को तोड़ दिया जाये क्योंकि यह सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर रही ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राष्ट्रीय परिषद् के अतिरिक्त बहुत सी विभागीय परिषदों और कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों जैसी संयुक्त परिषदों के समक्ष प्रस्तुत विवादों पर विचार-विमर्श करने और पारिश्रमिक बातचीत से उनका समाधान करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में ऐसी परिषदों की अनेक बैठकें हुई हैं । आपसी बातचीत द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिए राष्ट्रीय परिषद् की उप-समितियों, मंत्रियों की समिति और राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी